>

Title : Need to make provision in Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme for appointment of 300 watchmen to check the threat posed by wild animals to standing crops in Himachal Pradesh.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से जंगली जानवरों एवं बंदरों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बहुत वृद्धि हुई है। इसके कारण हर वर्ष करोड़ों रूपए की फसल बर्बाद हो रही है। जंगली जानवरों से तंग आकर बहुत से किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक ने वन परिक्षेत्राधिकारियों को बंदरों को मारने के परमिट जारी करने, बंदरों की संख्या को काबू करने के लिए उन्हें पकड़कर दूर-दराज के क्षेत्रों में छोड़ने तथा उनकी नसबंदी करने के कारगर उपाय किए हैं, परन्तु समस्या काबू से बाहर हो रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बंदरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जंगली जानवरों एवं बंदरों से फसलों की रखवाली के मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके ऐसी व्यवस्था करें, जिससे महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ में कम से कम 300 वॉचमैन नियुक्त किए जा सकें।